नरेगा ने मन मोहा मध्य प्रदेश का

जमीनी हालत-8

ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) की सफलता के कारण भी ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में काफी वोट मिले. इसीलिए हम पेश कर रहे हैं नरेगा का लेखा-जोखा. इस सीरीज में हम इस योजना की जमीनी हालत बताने की कोशिश कर रहे हैं. आप पढ़ चुके हैं झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र का हाल. आज पढ़िए मध्यप्रदेश के बारे में.

हिन्दुस्तान

दिनेश गुप्ता भोपाल

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जो अप्रत्याशित परिणाम मिले हैं, उसमें नरेगा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

राज्य की 29 में से बारह सीट कांग्रेस को मिली हैं। कांग्रेस को यह मुकाम लगभग दो दशक के बाद हासिल हुआ है। विकास संवाद केन्द्र के प्रमुख सचिन जैन भी यह मानते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में गए चुनाव परिणामों में नरेगा का भी योगदान है। चुनाव प्रचार के दौरान नरेगा के बारे में किए गए अध्ययन में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि योजना में भ्रष्टाचार भी काफी है। आधे से ज्यादा जॉबकार्ड धारकों के खाते नहीं खुले हैं। पोस्ट ऑफिस भी मजदूरी के पैसे का पूरा भुगतान नहीं कर रहा है। कानून के मुताबिक लोगों को काम भी नहीं मिल रहा है। डिण्डोरी जिले में 152 से अधिक बैगा आदिवासियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है।

मध्य प्रदेश में नरेगा योजना पूरी तरह से नौकरशाहों के हाथ में है। मुख्य सचिव सशक्त समिति के अध्यक्ष हैं। जॉब कार्ड खरीदे जाने के भी कई मामले हैं। छतरपुर जिले की राजनगर तहसील कन्हैया अहिरवार की तकलीफ यह है कि वर्ष 2008 में उसे पुलिया निर्माण के काम में लगाया गया लेकिन मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं हुआ। सिवनी जिले के कुरई विकास खंड में ठेकेदार कार्ड किराए पर लेकर योजना में काम कर रहे हैं। कई स्थानों पर जॉब कार्ड सरपंच के कब्जे में होने की शिकायतें भी मिलती रही हैं। मजदूरी की दर भी अलग-अलग है। कई लोग शिकायत करते हैं कि पूरे सौ दिन भी काम नहीं मिल पाता। इसके बाद भी राज्य में योजना की जनक कांग्रेस को चुनाव में काफी लाभ हुआ है। इससे शायद

नरेगा के बढ़ते कदम

वर्ष 2008-2009	
योजना में शामिल जिले	50
केन्द्र से प्राप्त राशि	3815 करोड़ 26 लाख 73 हजार रु.
राज्य का अंश	505 करोड़ 99 लाख 86 हजार रु.
उपलब्ध राशि	4809 करोड़ 87 लाख 22 हजार रु.
व्यय राशि	3551 करोड़ 86 लाख 71 हजार रु.
जॉबकार्डधारक परिवार	1 करोड़ 12 लाख 29 हजार 546 रु.
रोजगार प्राप्त परिवार	52 लाख 4 हजार 924 रु.
वित्तीय वर्ष में पूर्ण कार्य	1 लाख 82 हजार 864 रु.
वर्ष 2007-2008	
योजना में शामिल जिले	31
केन्द्र से प्राप्त राशि	2605 करोड़ 87 लाख 89 हजार रुपये
राज्य का अंश	289 करोड़ 50 लाख 84 हजार रुपये
उपलब्ध राशि	3302 करोड़ 38 लाख 14 हजार रुपये
व्यय राशि	2892 करोड़ 67 लाख 23 हजार रुपये
जॉबकार्डधारक परिवार	72 लाख 38 हजार 784 रुपये
रोजगार प्राप्त परिवार	43 लाख 46 हजार 916 रुपये
वित्तीय वर्ष में पूर्ण कार्यों की संख्या	1 लाख 36 हजार 3 रुपये